Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 8, Issue 1 | May. 2020 - October 2020 | pp. 1-5

वर्तमान सदी में चीनी वायरस और चीनी खतरे : एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. विकास शर्मा

हे.न.ग. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

शोध सारांश

वर्तमान सदी में जहाँ दुनिया भर में कोविड-19 से भय व तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है वहीं दूसरी ओर एक दूसरे से आर्थिक व सामरिक दौड़ में आगे बढने की प्रतिस्पर्धा थम नहीं रही है। हालांकि भारत की छवि पूरे विश्व में शांति प्रिय राष्ट्र की रही है, और इसकी भौगोलिक अवस्थिति दक्षिण एशिया में सामरिक आकर्षण का केन्द्र है। आज वर्तमान में समस्त राष्ट्र कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन सदैव से ही भारत के लिए एक अनसुलझी पहेली रहा है। चीनी खतरें लगातार स्थल हो या फिर समुद्र, चीन अपनी विस्तारवादी एवं अवसरवादी नीति के तहत भारत को कमजोर करने के लिए प्रयासरत हैं आज भारत की घेरेबन्दी करना चीन की प्रथम पहल बन गयी है और इसके लिए भारतीय सुरक्षा के किले को भेदने के लिए पडौसी राष्ट्रों में अपना राजनीतिकि और आर्थिक दखल बढा रहा है। जब विश्व व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है। चीन पाक सहयोग से भारतीय सीमाओं में हो रही गतिविधियों से सतर्क रहकर अपने समस्त पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को मधुर बनाने की नीति का संचालन और सावधान पूर्वक नेतृत्व की सख्त आवश्यकता है।

संकेताक्षर : *वायरस, कम्युनिज्म, ड्रैगन, विस्तारवादी, अतिक्रमण, टी.एम.ओ. मोबलाइजेशन*

प्रस्तावना

मानवता को खतरा परमाणु बम या मिसाइल से नहीं जितना इस चीनी वायरस से हैं। पिछली शताब्दी का सबसे खतरनाक वायरस स्पेनिश फ्लू था। 1918 में पृथ्वी पर हर तीसरा व्यक्ति इस वायरस से ग्रस्त था और एक साल में उसने पाँच से दस करोड़ लोगों की जान ली थी। इस समय कोरोना वायरस का दुनिया भर में खौफ है।[1] इस महामारी के चलते चीन के काले कारनामों पर गौर करना बेहद जरूरी है लेकिन वायरस उन तमाम खतरों में से महज एक है जो चीन के कारण दुनिया के सामने पेश आ रहे हैं। जितनी जल्दी दुनिया इन खतरों को पहचान लेगी उतने ही बेहतर तरीके से इन खतरों को पहचान लेगी उतने ही बहेतर तरीके से इन खतरों निपटने के लिए खुद को तैयार कर पाएगी और जैसा की चर्चिल ने कहा था, शांति के लिए तैयारी ही सुनिश्चित रास्ता है।[2] सच पर पर्दा डाल और झूठ के सहारे चीन बुहान से शुरू हुए वायरस पर काबू पाने में विफलता से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता रहा है। जबकि वायरस से दुनिया भर में लाखों लोगों की की जान जा चुकी है और आर्थिक तबाही का कोई ओर छोर नहीं है। लेकिन वायरस को लेकर छलकपट चीन के कम्युनिज्म से पेश आने वाला सबसे बुरा खतरा नहीं है। कहना चाहिए कि यह इसका सबसे स्पष्ट है कि वायरस की शुरूआत किसी भी देश से हो सकती है लेकिन जैसा खतरा और चुनौती चीन प्रस्तुत कर रहा है, कोई अन्य देश नहीं है।[3]

लद्दाख से अरूणाचल तक ड्रैगन की चालवाजी भारतीयों सीमाओं में अतिक्रमण और विस्तार की चीनी आकांक्षाएँ कभी छिपी नहीं है। इस संदर्भ में वह एक बहुत दूरगामी और शातिर रणनीति पर काम कर रहा है। पूर्वोतर तथा लद्दाख क्षेत्र में चीन द्वारा एक बहुत बड़े भारतीय हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया गया है। चीन धीरे-धीरे अपनी भौगोलिक सीमाओं को बढाता जा रहा है, और उन पर योजनाबद्ध ढंग से आधारभूत संरचना का निर्माण भी करता जा रहा है। एक लंबे समय से अरूणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा घोषित करता आ रहा है। उसे मालूम है कि यदि धीरे-धीरे इस प्रकार दुष्प्रचार भविष्य में कुछ वर्षों तक और किया

जाता रहा तो वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हुए इस क्षेत्र को झपट लेगा। उस समय ये दुष्प्रचार अपनी उसे अंतराष्ट्रीय समुदाय को संतुष्ट करने में काम आयेगा और उसके लिए अपने अतिक्रमण ओर विस्तारवादी नीति को वैधानिक जामा पहनाना आसान होगा।[4]

इस सन्दर्भ में चांग्पा नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चोरिग दोर्जे कहते है, कि चीनी अपने गडरियों पर रोक लगाने के बजाय वह भारतीय सीमा में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सीमा पर रोक-टोक होने पर इसके बचाव मे आ जाते हैं। चीनियों की कब्जा जमाने की यह नीति पुरानी है। डोकलाम में ही चीनियों ने यही दावा किया था।

चीन केवल लद्दाख में ही नहीं बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई इलाकों में यथा स्थिति बदलने की तैयारी में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के खेमकुला में जहाँ वह नियंत्रण रेखा के समीप सड़क बना रहा है। वही उत्तराखण्ड के ठीक सामने पड़ने वाले कैलाश मानसरोवर पर्वत के पीछे उसने ग्राउंड टू एयर मिसाइल डिफेंस स्टिम तैनात कर दिया है। यह सीमा से मात्र 19 किलो मीटर की दूरी पर है। पिछले दिनों चीन ने यहाँ 1000 सैनिकों की भी तैनाती की थी। इसके बाद नेपाल के माध्यम से भारत का चीन में उलझाए रखा हैं वही सिक्किम के डोकाला और नाकुला से 100 किमी में ऑल वेदर हेलीपैड का निर्माण किया है, और यहाँ 50 किमी में ही मिसाइल साइट की है।[6]

चीनी सेना ने भारत की सीमा से लग्ते सभी एयरबेस एक्टिव स्थिति में है। चीन ने काशगार बसे पर एच 6 बम्बर तैनात किया है तो वहीं होतान एयरबेस पर 20 युद्धक विमान की तैनाती की है। यह एयरबेस सीमा से करीब 325 किलोमीटर पर स्थित है। चीन जिस तरह से भारत को सीमा पर उकसा रहा उसके पीछे लंबी तैयारी है। एक तरफ चीन कई दौर की सैन्य वार्ता कर चुका है, दूसरी तरफ सभी फ्रंट पोजिशन पर निर्माण कार्य व ऑप्टीकल फाइबर बिछा रहा है। पंगौग्त्सो झील के पास नई गन पोजिशन बनाई है।[7]

वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ गलवान घाटी पैगोंग झील क्षेत्र ओर कई अन्य स्थानों पर चीन के आकस्मिक हमले की पृष्ठभूमि का एक सुनियोजित दूरदर्शिता का परिणाम है। यह राष्ट्रपति शी जिनपींग की ओर से जारी किए गए एक नए मोबलाइजेशन आर्डर पर काम का नतीजा था। चीन की और से मई की शुरूआत से मध्य से एलओसी पर आकस्मिक हमले की कई घटनाएं कई सौ किलोमीटर की दूरी पर कई जगह लगभग एक साथ हुई कुछ ही दिन में कुछ घंटों के अंतराल के साथ हुई घटनाओं की टाइमिंग से लगता है कि इसमें उच्च स्तर का समन्वय ओर योजना शामिल थी।[8]

जनवरी के अंत में और फरवरी के शुरूआत में पीएलए ने शिंजियांग में लद्दाख बार्डर पर वार्षिक अभ्यास के लिए एकत्रित हुए थे। इस वर्ष पीएलए सैनिक पहली बार सीमा के बहत नजदीक पहुँच गए इसी कारण अप्रैल में सैनिकों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा था और यह कदम बहुत स्पष्ट था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति शी ने वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में सैन्य प्रशिक्षण को मजबूत करने और तत्परता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए नए ट्रेनिंग मोबाइलाइजेशन आर्डर (टीएमओर) पर हस्ताक्षर किए जो टकराव प्रशिक्षण का आह्वान करती है। चीन के नाटकीय रूप से वार्षिक अभ्यासों से इसके तैनाती पैटर्न को बदला है, न केवल भारत के साथ बल्कि दक्षिण चीन सागर में जापान ताईवान में भी तनाव बढा दिया है।[9] हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर का विवाद एशिया प्रशान्त क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा की एक नयी चुनौती बनकर उभरा है। एक तरफ इस क्षेत्र में चीन अपना परम्परागत अधिकार बताते हुए अपनी सैनिक उपस्थिति व गतिविधि बढा रहा है। वहीं अमरीका तथा अन्य क्षेत्र देश वहाँ आवागमन की स्वतंत्रता पर जोर दे रहे हैं। यह तनाव इस क्षेत्र में सामरिक क्षेत्रीय बदलाव का परिणाम है। चीन के दक्षिण में स्थित दक्षिण चीन सागर इसका सबसे तनाव मुक्त क्षेत्र बनता जा रहा है। इसका कारण दक्षिण चीन सागर का सामरिक महत्व है। स्पष्टत चीन का अधिकांश समुद्री व्यापार व ऊर्जा आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना दक्षिणी गलियारा आथवा बैकयार्ड समझता है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 35 लाख वर्ग किलोमीटर है।

दक्षिण चीन सागर में तेल प्राकृतिक गैसें तथा खनिज पदार्थों के भी पर्याप्त भंडार पाये जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में 11 विलियन बैरल तेल तथा 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैंस के भंडार स्थित है इसके साथ ही यह क्षेत्र विश्व व्यापर व समुद्री आवागमन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चीन का अर्थिक विकास भी समुद्री मार्गो की सुरक्षा व उपलब्धता पर निर्भर करता है। चीन एशिया प्रशान्त क्षेत्र में गत कुछ वर्षो से अपने प्रभाव में विस्तार का प्रयोग कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में उसकी सैनिक गतिविधियाँ उन्ही प्रयासों का एक अंग है।[10]

दक्षिण चीन सागर पर कब्जे की नीयत रखने वाले चीन ने हैनान द्वीप में एक भूमिगत सैन्य बेस बना लिया है। अमरीकी कंपनी प्लेनेट लैब्स ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह खुलासा करते हुए बताया कि इस यूलिन सैन्य बेस की भूमिगत सुरंग के प्रवेश द्वारा

से 18 अगस्त को एक प्रकार की 093 परमाणु चलित अटैक पन्नडुब्बी गुजरती हुई देखी है। सैन्य विशेषज्ञों ने दावा किया कि यह रहस्यमय भूमिगत सैन्य बेस चीन के सैन्य हार्डवेयर का एक साधन हो सकता है जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है।[11]

चीन व पाकिस्तान का सामरिक गठजोड़ अफगानिस्तान से अमरीका की वापसी तथा वहाँ पाकिस्तान समर्थित तालिबान शासन की स्थानपा उसे और अधिक चिन्ता का कारण बन सकता है। इसलिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा है यह समाधान और कुछ नहीं है बल्कि वहाँ अपने समर्थन वाले शासन की स्थापन करना है। चीन की वर्तमान नीति पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध खुला समर्थन देने की नीति है, अपनी नीति में चीन पाकिस्तान को भारत के साथ बराबरी करने में पूरी मदद कर रहा है। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे को सभी मौसम के दोस्त मानते है। पाकिस्तान में चीन के बढते समरिक हितों के कारण पाकिस्तान चीन के सामरिक सम्बन्धों में गहराई बढ़ती जा रही है।[12]

चीन न केवल सीमाओं के कई बिदुओं पर तनाव और अस्थिरता फैला रहा है। बल्कि वह नेपाल और भूटान को भी उकसा व धमाकाकर रहा भारत की परेशानियों को बढाने में लगा हुआ है। पिछले दो महीने से भारत चीन की पश्चिमी सीमा में सैनिकों की लगातार भिड़ंत हो रही थी तो नेपाल ने भी आक्रमण तरीके से भारत के लिपुलेख लिंग्प्याधूरा और काला पानी क्षेत्रों को हड़पने की कोशिश की। इसके अलावा प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली चीन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए भारत के प्रति तल्ख तेवर व कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2016 में जब कई वामपंथी घटकों के मिलने से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ तब से उसके अंदरूनी गुटों में तनातनी चल रही है और लगातार चीन इन गुटों को एकजुट रखने की कोशिश में सबसे आगे रहा है। वर्ष 2018 से तो काठमांडू में चीन की राजदूत हाउ पान कि लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी की कहर परेशानी को सुलझाने में उनकी मुख्य भूमिका रहती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ नेपाल के इस आक्रमक रूप को चीनी की भारत नीति का ही हिस्सा मानते हैं।[13]

भूटान में भी चीन लगातार उपने प्रभाव को बढ़ाने में लगा हुआ है।। परन्तु 2017 मे 10 सप्ताह तक चलने वाले डोकलाम गतिरोध के बाद भूटान चीन की रणनीति को समझा गया है। परिणाम यह है कि 1984 से शुरू हुई सीमावार्ता अब स्थगित हो गई है। इसका 24वाँ दौर 2016 में हुआ था तब से दोनों की सीमा को लेकर बातचीत नहीं हुई । इससे नाराज होकर चीन ने पिछले माह भूटान के एक नए क्षेत्र पर भी दावा पेश कर दिया। ग्लोबल एनवायरमेंट फेसिलिटी काउंसिल ने भूटान को जब उसकी सार्क्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वितीय सहायता देने की पेशकश की तो चीनी प्रतिनिधि ने यह कहकर विरोध किया कि यह भूमि तो चीन की है। इससे पूर्व केवल भूटान की उत्तरी पश्चिमी सीमा को लेकर विवाद था। वहाँ भी चीन इस उत्तरी क्षेत्र के 495 वर्ग किमी के दावे को छोड़ने के लिए तैयार था बशर्ते भूटान उसे डोकलाम पठार में उसके 269 वर्ग किलोमीटर के दावे में से केवल 100 वर्ग किलोमीटर भूमि दे दे । वह इसलिए क्योंकि डोकलाम क्षेत्र में चीन को ज्यादा जगह मिलने से वह भारत के सिलिगुडी कॉरिडोर पर अपना प्रभाव बढा सकेगा और उससे भविष्य में अपना प्रभाव बढा सकेगा और उससे भविषय में उसके लिए भारत के पूर्वोतर क्षेत्र को अलग थलग करने की क्षमता संभव हो सकती है। पूर्वी भूटान में यह 740 वर्ग किलोमीटर का नया दावा उसके भारत के अरूणाचल प्रदेश पर बदलते रवैये का हिस्सा है।[14]

अमरीकी विदेश मंत्रायलय ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) के विरुद्ध चीन के परमाणु अस्त्र परीक्षण को लकर चिंता व्यक्त की है। यह तो सिर्फ पिछले महीने का हाल है। चीन का तो वर्षो की बर्बरता और आक्रमता का ट्रैक रिकार्ड है। चीन ने अपनी सैन्य क्षमताओं को व्यापक पैमाने पर बढ़ाया है। ओरयेलियन सर्विलांस राष्ट्र (जॉर्ज ओरवेल के अनुसार शासन द्वारा राष्ट्र में ऐसी स्थितयाँ पैदा करना जो मुक्त और स्वतंत्र समाज के कल्याण के प्रति विध्वंशकारी हो, का निर्माण किया है और 10 लाख से अधिक अल्पसंख्यक नागरिकों को रिएजुकेशन शिविरों में धकेल दिया है। वैश्विक रूप से चीन ने अभूतपूर्व स्तर तक जाकर बौद्धिक सपंदा की चोरी की है। संयुक्त राष्ट्र की एजेसियों जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कब्जा जमाया है, अपने लाभ के लिए खतरनाक ऋण समझौते गरीब राष्ट्रों पर थोपे हैं। एशियाई पड़ोसी देशों का उत्पीड़न किया है।[15]

भारत व मालदीव के बीच ऐतिहासिक व घनिष्ठ बहुपक्षीय सम्बन्ध रहे हैं। 1965 में मालदीव की आजादी के बाद से ही भारत वहा विकास साझेदारी को मजबूत करता रहा है। लेकिन मालदीव की घरेलू राजनीति में बदलाव के कारण चीन को वहा अपना सामरिक प्रभाव बढाने का अवसर मिला। यामीन शासन चीनी समर्थक तथा भारत विरोधी था। 2013 से 2015 तक इस शासन काल में चीन को मालदीव में अपने पैर पसारने का अवसर प्राप्त हुआ इसका फायदा उठाकर चीन ने कई महत्वपूर्ण द्वीपों पर पड़े पर अधिकार

कर लिया। उल्लेखनीय है कि मानदीव में चीन का बढ़ता हुआ सामरिक प्रभाव भारत की सुरक्षा की दृष्टि से घातक है। क्योंकि मालदीव भारत के लक्षद्धीप से केवल 700 किलामीटर तथा भारत की मुख्य भूमि से केवल 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम की ओर जाने वाले भारत के व्यापार मार्ग भी मालदीव के पास से गुजरते हैं। अतः मालदीप में चीन सामरिक उपस्थिति भारत के लिए चीन खतरा है, विचारणीय है।[16]

हिन्द महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका विस्तार पूर्व में अदन की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी तट तक है। यह महासागर भारत की सुरक्षा तथा अर्थिक हितों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन हाल के दशकों में हिन्द महासागर में चीन की पहुँच निरन्तर बढ़ रही है। हिन्द महासागर के दक्षिणी तथा पश्चिमी हिस्से में चीन की पहुँच तथा प्रभाव पहले से बना हुआ था लेकिन हाल में ही चीन हिन्द महासागर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अपने पैर जमाने का जो प्रयोग से किया है। वह सबसे ज्यादा भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।[17]

म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित एक छोटा देश है। तथा पूर्व में इसकी थल सीमाएँ भारत के चार राज्यों अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम व मेघालय से मिलती है। वर्तमान में म्यांमार निरन्तर चल रहे जातीय संघर्ष तथा वहाँ सेना द्वारा रोंहिग्या अल्प संख्यकों के प्रति की गई हिंसा के कारण विश्व स्तरर पर अलगाव का सामना कर रहा है। चीन ने म्यांमार के इस अलगाव का फाायदा उठाकर उसका राजनीतिक समर्थन आरम्भ कर दिया है। चीन द्वारा पाकिस्तान की तर्ज पर म्यांमार में भी चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे की शुरूआत इसके अन्तर्गत चीनी अपनी सीमा से चीन को म्यांमार के दक्षिण में स्थित क्याउकफिउ बन्दरगाह तथा यातायात उद्योग तथा अन्य ढाँचागत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। क्याउकफिउ बन्दगाह हिन्द महासागर में बंगाल की खाडी में स्थित होने के कारण भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।[18]

भारत चीन सीमा विवाद लम्बे समय से चला आ रहा है। यदि सैन्य विवाद के अब तक घटनाकम पर नजर डालें तो पिछले 10 वर्षो के दौरान इस बार जैसा विवाद नहीं हुआ। जहाँ तक चीन का प्रश्न हैं, वह हमेशा की तरह मुंह में राम बगल में छुरी लिए बैठा है। धूर्तता में हमेशा इस पड़ोसी का कोई सानी नही। वर्ष 1962 में उसने हिन्दी चीन भाई-भाई का नारा लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को धोखा दिया और अब झुक झुककर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को। इतना फर्क जरूर है कि तब भारत को आजादी मिली ही थी और हम सैन्य दृष्टि से उतने मजबूत नहीं थे अब हालात ऐसे नहीं है। भारत चीन युद्ध के बाद हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है। कारगिल ताजा उदाहरण हैं।[19]

कोरोना संकमण फैलाने के लिए जिम्मेदार चीन को अलग थलग करना जारी रखना होगा। उग्र चीन का दाम करने के लिए कवाड (अमरीका जापन आस्ट्रेलिया और भारत) का सुरक्षावार्ता समूह और ऐसे ही समान विचारधारा वाले देशों के बहुपक्षीय क्षेत्रीय समूहों को मजबूत करना होगा। अमरीका के नेतृत्व में अंतराष्ट्रीय स्तर पर सहमति बननी होगी जो पाकिस्तान के नायाब इरादों को नाकाम कर सके। हमें एलएसी और इसके आसपास के संवेदन शील इलाकों में सैन्य पराक्रम के संकेत देने होंगे मौजूद्रा त्रिपक्षीय समझौते भी फिर से समीक्षा करनी होगी। चीन के साथ युद्ध नहीं होगा समझोता करके सभी सीमा समस्या को हल करने की जरूरत है।[20]

निष्कर्ष

समग्रत कहा जा सकता है कि चीनी वायरस और चीनी खतरों से भारत चीन संबंध सदा के लिए बदल गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री इस संबध में चेता चुके हैं। नए जमाने के युद्ध और समुद्री सीमा पर निकट भविष्य को सीमित पारम्परिक संघर्ष की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सेनाओं को इस क्षण पूरे साजो समान व तैयारी के साथ चाक चौबद रहना होगा। कुशल नेतृत्व और पर्याप्त संसाधनों के साथ हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते है। पाकिस्तान द्वारा छ्दम युद्ध और चीनी सेना द्वारा सीमा पर झडपों ने हमारे सैनिकों का युद्ध कौशल निखरता ही है। कुल मिलाकर देश के नेतृत्व का समर्थन करते हुए पूरे देश को एक स्वयं में चीन के दुस्साहस का मुंह तोड़ जबाब देना होगा और यह अभी ही करना होगा क्योंकि इसी आधार पर चीन के साथ भारत के भावी संबंधों की दिशा निर्धारित होगी।

सन्दर्भ सूची

1. अमर उजाला, 24 फरवरी 2020, देहरादून
2. राजस्थान पत्रिका, 9 मई 2020, पृ.सं. 10
3. राजस्थान पत्रिका, 4 मई 2020
4. पंकज के. सिंह, भारतीय विदेश नीति के आयाम, पृ.सं. 66
5. राजस्थान पत्रिका, 1 सितम्बर 2020, पृ.सं. 9
6. दैनिक जागरण, 5 सितम्बर, पृ.सं. 01
7. दैनिक जागरण, 5 सितम्बर, पृ.सं. 01
8. राजस्थान पत्रिका, 14 जुलाई 2020
9. राजस्थान पत्रिका, 14 जुलाई 2020
10. विश्व परिदृश्य, प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर 2018, पृ.सं. 72

11. प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल 2019, पृ.सं. 72
12. नेपाल के कंधे पर चीन का निशाना, स्वर्ण सिंह, राजस्थान पत्रिका, 09 जुलाई 2020
13. उपर्युक्त
14. नेपाल के कंधे पर चीन का निशाना, स्वर्ण सिंह, पूर्वोक्त
15. हेली, निकी, वायरस के आलावा चीन से और भी खतरे, राजस्थान पत्रिका, मई 2020
16. प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी 2019, पृ.सं. 75-76
17. प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल 2020, पृ.सं. 69
18. विश्व परिदृश्य, प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल 2020, पृ.सं. 20
19. पीठ में छुरा घोपने की चीन की पुरानी आदत, राजस्थान पत्रिका, 5 सितम्बर 2020
20. एलएसी पर चीन की कुटिल नीतियों का होगा करारा जबाब, अरूण सहानी, 5 सितम्बर 2020